



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ 1933 (श०)
(सं० पटना 339) पटना, बुधवार, 20 जुलाई 2011

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई 2011

सं० 11/मु० मुकदमा नीति-02/2011-49 (11) रा—1. विधि विभाग के संकल्प संख्या NoA/AJ-20/2010-1853/J दिनांक 31 मार्च 2011 (विषय :-बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011) की कंडिका संख्या-2.1 के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरणों, जाँच आयोगों, मध्यस्थता एवं वैकल्पिक विवाद निराकरण प्रक्रियाओं के नियमित अनुश्रवण तथा सरकारी मुकदमों के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए श्री महिपाल सिंह यादव, उप-सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. उपर्युक्त राज्य मुकदमा नीति की कंडिका-2.4 (b) के आलोक में विभाग स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है :-

- (1) डॉ० सी० अशोकवर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- (2) श्री आनन्द किशोर, विशेष सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप/निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- (3) श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- (4) श्री सुरेश पासवान, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

यह समिति विभाग से सम्बन्धित सभी मुकदमों का प्रति माह अनुश्रवण एवं समीक्षा करेगी। इस समिति को वैसे वादों के सम्बन्ध में जिनमें वृहद प्रशासनिक प्रभाव या अत्यधिक वित्तीय अंतर्निहितताएँ न हों, के सम्बन्ध में

निर्णय लेने का अधिकार होगा। अन्य वादों में यह समिति राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को अपनी अनुशंसाओं के साथ मामला संदर्भित कर देगी।

3. उपर्युक्त राज्य मुकदमा नीति की कंडिका-4.A(1) के आलोक में निम्न प्रकार से विभागीय शिकायत निवारण समिति गठित की जाती है :-

- (1) डॉ सी0 अशोकवर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- (2) श्री आनन्द किशोर, विशेष सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण/निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- (3) श्री राम बाबू सिंह, संयुक्त निदेशक, चकबंदी
- (4) श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- (5) श्री महिपाल सिंह यादव, उप-सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- (6) श्रीमती कल्पना कुमारी, सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण

विभागीय कर्मचारियों से अपेक्षा की जाएगी कि न्यायालय की शरण लेने के पूर्व इस समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन उपस्थापित करें। समिति द्वारा त्वरित रूप से नियमानुसार मामले का निस्तार किया जाएगा। विभाग में शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए प्रति माह समिति की एक बैठक होगी। समिति का प्रयास होगा कि प्रभावशाली ढंग से शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करते हुए बड़ी संख्या में परिहार्य वादों को दायर होने से रोका जा सके।

इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सी0 अशोकवर्धन,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 339-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>